

जल समाचार

यह भी जानिये

जल पुरुष राजेंद्र सिंह को स्टॉकहोम वाटर प्राइज

प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह को भारतीय गांवों में जल संरक्षण प्रयासों और समुदायों को सशक्त करने के लिए 2015 के प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज से नवाजा गया। स्वीडन के किंग कार्ल गुस्ताफ 2015 के विश्व जल सप्ताह के दरम्यान 26 अगस्त को एक रॉयल अवार्ड सेरेमनी में राजेंद्र सिंह को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इसके तहत उन्हें 1,50,000 डॉलर की धनराशि प्रदान की जाएगी यह पुरस्कार 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की ओर से दिया जाता है। एक बयान में कहा गया कि 'जल पुरुष' के रूप में लोकप्रिय 1959 में जन्मे राजस्थान के श्री राजेन्द्र सिंह ने भारत के ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण सुधार और जरूरतमंद लोगों के रहन-सहन को बेहतर बनाने का साहसिक प्रयास किया।

गंगा सफाई अभियान में कई देश दिखा रहे रुचि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नमामि गंगे' अभियान का असर विश्व के संपन्न देशों पर भी दिखने लगा है। कई देशों ने आगे बढ़कर गंगा स्वच्छता अभियान से जुड़ने में दिलचस्पी दिखाई है।



नमामि गंगे



जापान, हालैंड, जर्मनी, कनाडा, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सरीखे देश भारत से जुड़कर गंगा की निर्मलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस प्रयास में इंग्लैंड के नदी सफाई विशेषज्ञों के एक दल ने गंगा स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। तीन सदस्यीय इस दल के साथ भारत में इंग्लैंड के उप-उच्चायुक्त जूलियन इवांस और ऊर्जा सुरक्षा पर सेंकंड सेक्रेटरी मेलिसा एल्से भी थीं। इससे पहले कई देशों के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के सामने गंगा को लेकर अपनी मंशा जताई है। इस दल ने केंद्रीय मंत्री के सामने गंगा स्वच्छता से जुड़ने की अपनी मंशा व्यक्त करते हुए तकनीकी सहयोग और आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। दल ने इंग्लैंड की टेम्स नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अपनाए गए उपायों का एक पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी किया है।

यमुना में पूजन सामग्री फेंकी तो रुपये 5000 जुर्माना

पूजा-पाठ के बाद अगर आप फूलमाला समेत पूजन सामग्री को यमुना नदी में प्रवाहित करते आए हैं तो सावधान हो जाइए। अब ऐसा करने पर आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। यमुना नदी को निर्मल करने के लक्ष्य के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यह सख्त आदेश दिया।

एनजीटी चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के आदेश के मुताबिक यमुना नदी में पूजन सामग्री या किसी भी तरह का कचरा फेंकना प्रतिबंधित होगा और नियम का उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

नदी में मलबा डालने पर लगाया जुर्माना

परियोजना निर्माण का मलबा नदियों में डालने वाली कंपनियों पर कार्रवाई होने लगी है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने अलकनंदा में मलबा डालने पर पीपलकोटी-विष्णुगड जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही हिंदुस्तान कंपनी पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया है।

गंगा को निर्मल बनाने पर विचार

गंगा की अविरल धारा और निर्मलता सुनिश्चित करने के साथ ही संरक्षण को लेकर जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने विचार के लिए एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजा है। इस पर पीएम की मुहर लगते ही सरकार की ओर से गंगा संरक्षण कार्यक्रम पर टोस कदम उठाए जाएंगे। एक कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि गंगा की निर्मलता और अविरलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से जल्द समयबद्ध कार्यक्रम



यह भी जानिये

की घोषणा की जाएगी। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि गंगा में शोधित या अशोधित किसी तरह का पानी नहीं जाए। वहीं उन्होंने उद्योग जगत से अपील की है कि वे अपने इस्तेमाल के लिए नदी से पानी लेने की जगह अपने शोधित जल का ही इस्तेमाल करें। प्रत्येक मौसम में नदियों में साल भर पानी का प्रवाह बना रहे, इसे भी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

140 नाले रोके जाएंगे गंगा में गिरने से क्या होगा खास

- ◆ गंगा किनारे हरियाली बढ़ाने के लिए किया जाएगा कार्य।
- ◆ रेड क्रॉस की तर्ज पर गंगा वाहिनी तटरक्षक का होगा गठन।
- ◆ रेत खनन पर बनेंगे सख्त नियम।
- ◆ प्रदूषण नियंत्रण करने को नेशनल गंगा मॉनिटरिंग सेंटर होगा तैयार।

गंगा सफाई में जुटी सरकार ने गंगोत्री से गंगासागर तक इसे प्रदूषित करने वाले नालों की गंदगी को नदी में गिरने से पूरी तरह रोकने का फैसला लिया है। करीब 140 नालों की गंदगी को गंगा में गिरने से रोकने का काम शुरू हो चुका है। वहीं गंगा किनारे अस्थि विसर्जन पर भी पाबंदी लगेगी। हालांकि गंगा सफाई से जुड़ी तमाम नीतियों पर कदम बढ़ाने के साथ आम आदमी की आस्था का खयाल भी रखा जाएगा। श्रद्धालुओं को पूजा सामग्री गंगा में विसर्जित करने से नहीं रोका जाएगा।

तीन साल में पूरा होगा क्लीन गंगा प्लान

◆ अब पूरी फंडिंग करेगी केंद्र सरकार:

प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 'क्लीन गंगा प्लान' तीन वर्ष में पूरा होगा। लगभग बीस हजार करोड़ की योजना वर्ष 2018 तक मूर्तरूप ले लेगी। यह घोषणा रविवार को काशी में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा भारती ने की।

महापौर, जन प्रतिनिधियों व आला अधिकारियों के साथ दो चरणों में बैठक कर उन्होंने क्लीन गंगा प्लान व नमामि गंगे से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। योजना से जुड़े कुछ बिंदुओं पर उन्होंने अफसरों की क्लास भी ली। जन प्रतिनिधियों से मंत्री की अपेक्षा थी कि वे योजना के क्रियान्वयन में अपनी शत फीसद भागीदारी सुनिश्चित करें। यह भी कहा कि वह 15 दिन पर काशी का दौरा कर योजनाओं की समीक्षा करेंगी। पूरे देश में क्लीन गंगा प्लान का केंद्र वाराणसी ही होगा। कहा कि अब पूरी फंडिंग केंद्र करेगा। बैठक के बाद पत्रकारों को मंत्री महोदय

उमा ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन का खाका तैयार है। पहले बीस हजार करोड़ के क्लीन गंगा प्लान को सात वर्ष में मूर्तरूप लेना था। अब इसे तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा कार्ययोजना 29 वर्ष बाद भी परवान क्यूं नहीं चढ़ी के सवाल पर केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास व गंगा पुनरुद्धार मंत्री उमा ने कहा कि पहले बजट में 70 फीसदी केंद्र व 30 फीसदी राज्य को खर्च करना था। अलग-अलग दलों की सरकार होने के कारण राज्य धन देने में आनाकानी करते थे। अब क्लीन गंगा प्लान की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी।

बदलते परिवेश में जल संसाधन प्रबंधन की भूमिका

◆ जल संरक्षण एवं गुणवत्ता पर गोष्ठी में होगा मंथन

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच) रुड़की द्वारा पांचवीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी का आयोजन 19-20 नवम्बर को किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ प्रतिभाग करेंगे। संगोष्ठी में जल की मात्रा, गुणवत्ता, मांग, उपयोगिता और आपूर्ति पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें देश के दीर्घकालिक विकास के लिए जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उपयुक्त एवं बेहतर प्रबंधन के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए संगोष्ठी में सभी व्याख्यान हिंदी में दिए जाएंगे। संगोष्ठी में सतही जल निर्धारण एवं प्रबंधन, भूजल निर्धारण एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सूखा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, नदियों में अविरल एवं निर्मल धारा बनाए रखने के लिए उपाय, पर्वतीय क्षेत्रों में जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन एवं पुनः प्रयोग आदि विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। एनआईएच हर चार साल में इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन करता है। इससे पहले वर्ष 2011 में इसका आयोजन किया गया था।

सावधान! खत्म होने को है भूगर्भ जल

दुनिया के करोड़ों लोगों का गला तर करने वाले स्वच्छ भूगर्भ जल के स्रोत सूखने के कगार पर हैं। नासा के नए सेटेलाइट डाटा के अनुसार भारत, चीन, अमेरिका और फ्रांस स्थित दुनिया के सबसे बड़े 37 भूगर्भ जलस्रोतों में से 21 की स्थिति अति चिंताजनक है। पिछले एक दशक के दौरान इन जल स्रोतों से जितना पानी निकाला गया, उतना उसमें समाहित नहीं किया गया। 13 अन्य भूगर्भ जलस्रोतों की स्थिति गंभीर हो चली है। पानी की समस्या यहां कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है।

जल है तो कल है

जल हमारे जीवन का आधार है लेकिन इस प्राकृतिक संसाधन के बेपरवाह उपभोग से भविष्य में जल संकट का बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। जलीय संसाधनों का जीवन के हर क्षेत्र मसलन गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और सुरक्षित पर्यावरण में अहम योगदान है। इसीलिए तो टिकाऊ विकास की बुनियाद जल पर ही खड़ी है। इसीलिए आसन्न संकट के बीच आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की हर एक बूंद का संरक्षण एकमात्र उपाय है:

हिस्सेदारी

- ◆ 18% कुल वैश्विक आबादी में देश की हिस्सेदारी।
- ◆ 4% देश के जल स्रोतों की वैश्विक हिस्सेदारी।

देश में दोहन

- ◆ 40% इससे भी अधिक सतह पर उपलब्ध जल का हर साल दोहन होता है।
- ◆ 80% उत्तरी पश्चिमी हिस्से में सतह जल के उपभोग का स्तर।

दस करोड़

लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे जिलों में रहते हैं जहां के जल में कम से कम एक प्रदूषक तत्व तय मानकों से अधिक पाया गया।



समस्या

- ◆ 54% देश का जल दबाव क्षेत्र। यानी किसी न किसी रूप में जल संकट मौजूद।
- ◆ 60 करोड़ देश के लोगों पर भविष्य में सतह जल आपूर्ति का मंडराता खतरा। सिकुड़ती सप्लाई का कृषि पर पड़ेगा गंभीर खतरा क्योंकि 90 प्रतिशत खेती इसी पर निर्भर।

भूजल

◆ केंद्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू. बी.) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पिछले एक दशक (2003-13) की तुलना में 56 प्रतिशत कुओं के जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई।

बढ़ता बोटलबंद पानी

◆ 10 हजार करोड़ डॉलर का वैश्विक कारोबार।

◆ देश में प्रति व्यक्ति बोटलबंद पानी की खपत पांच लीटर सलाना जबकि विश्व का औसत 24 है।

◆ भारत बोटलबंद पानी का दसवां बड़ा उपभोक्ता।



◆ देश में 2013 तक यह 60 अरब रुपये का कारोबार था। 2018 तक 160 अरब का अनुमान।

◆ 40 फीसद इसका बाजार पश्चिमी भाग तक जबकि पूर्वी भाग में केवल 10 फीसद है। सर्वाधिक बोटलिंग प्लांट दक्षिण में हैं।

गंगा तटों पर जड़ी-बूटी लगाने पर हो रहा विचार

◆ इको टास्क फोर्स को दी जाएगी पौधे लगाने की जिम्मेदारी।

◆ आयुष मंत्रालय लगाएगा प्रोसेसिंग इकाइयां।

उत्तराखंड में जल्दी ही गंगा के तटों पर

जड़ी-बूटियां लगाने पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं इन जड़ी-बूटियों से यहां दवाएं बनाने की इकाइयां भी लगा सकता है। इस काम में पूर्व सैनिकों की 'इको टास्क फोर्स' शामिल होगी। इस फोर्स के सदस्यों को पौधा लगाने से जुड़ी गतिविधियों में लगाया जाएगा। यह राजग सरकार की स्वच्छ गंगा परियोजना का ही हिस्सा होगा।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय इस बारे में एक प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे हैं। सरकार की जैविक कृषि शाखा भी इसमें शामिल होने की तैयारी में है। एक अधिकारी ने कहा, हम लोग आयुष मंत्रालय से बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारे बीच (दोनों मंत्रालयों) सहमति पत्र भी तैयार हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, इको टास्क फोर्स संभवतः तीन माह में काम करने लगेगा और इसे नदी में कचरा डालने से रोकना और पौधे लगाने सहित तीन प्रमुख जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मौजूदा योजना के अनुसार, ये पौधे देहरादून शोध संस्थान से लेकर उत्तराखंड में गंगा तटों पर लगाए जाएंगे। इको टास्क फोर्स पौधे लगाएगा वहीं आयुष मंत्रालय जड़ी बूटी की प्रोसेसिंग इकाइयां लगाएगा। जल संसाधन मंत्रालय हर्बल उत्पादों के विपणन में सहायता करेगा। पूरी योजना को अगले साल अक्टूबर तक कार्यरूप दे दिया जाएगा। इसका मकसद स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रस्तावित इको टास्क फोर्स सेना की एक क्षेत्रीय इकाई होगी जिसमें चार बटालियन होंगी। हर बटालियन का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय का एक कर्नल रैंक का अधिकारी करेगा और इसके जवान पूर्व सैनिक होंगे। इस फोर्स में कुल करीब 1600 लोग होंगे। पहले साल इस फोर्स के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है। किसी नदी को स्वच्छ करने में रक्षा बलों को शामिल करने का इसे देश में पहला मामला बताया जा रहा है। इन बटालियनों को सबसे पहले गंगा के सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इनमें कानपुर-वाराणसी, मथुरा-वृंदावन और हरिद्वार के साथ इनकी सेवाओं का दिल्ली में भी इस्तेमाल किया जाएगा।

देहरादून में नमामि गंगे के लिए कसरत

◆ महाभियान का खाका बना रहा एफ.आर.आई.

◆ देश के ग्यारह राज्यों में लागू होगा प्रोजेक्ट गंगा को स्वच्छ, निर्मल बनाने को न सिर्फ गंदगी को उसमें जाने से रोका जाएगा, बल्कि उसके आस-पास ऐसी वानिकी का विकास हो, जिससे न सिर्फ गंगा स्वच्छ हो बल्कि हर्बल मेडिकल प्लांट के जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकें।



गंगा को साफ करने के महाभियान का खाका तैयार करने का श्रीगणेश देहरादून से शुरू हो गया है। इसके लिए एफ.आर.आई. में शुरू हुई दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। उन्होंने कहा कि गंगा मिशन की शुरुआत गंगा के उद्गम स्थल से करनी होगी। हिमालय क्षेत्र के वनों, वृक्षों, जलस्रोत व खेती के पुनरुद्धार से ही गंगा साफ हो सकती है। राज्य सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है।

युवाओं को मिलेगा काम

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि नमामि गंगे अभियान में उत्तराखंड में नदी किनारे औषधीय पौधों के प्रोसेसिंग हब विकसित किए जाएंगे। नमामि गंगे के तहत स्थानीय युवाओं को औषधीय पौधे लगाने का काम मिलेगा।

इकोलॉजी मजबूत करनी होगी

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पांच हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को भी सॉलिड वेस्ट निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। केंद्रीय मंत्री आयुष श्रीपद नायक ने कहा कि नमामि गंगे में औषधीय पौधे की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय खेल व युवा कल्याण मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने युवा कल्याण मंत्रालय को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक बड़ा सच है कि नदियां मर रही हैं। इसके लिए औद्योगिक प्रदूषण पर न सिर्फ पूरी रोक लगानी होगी, बल्कि सख्ती बरतनी होगी।

साभार:

अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान